

विचार बिन्दु

अज्ञानी होना मनुष्य का असाधारण अधिकार नहीं है बल्कि स्वयं को अज्ञानी जानना ही उसका विशेषाधिकार है। -राधाकृष्णन

आज़ादी का अमृतकाल आ गया मगर असमानता नहीं मिटी

संविधान में समानता और न्याय को स्वतंत्र भारत का आदर्श बना देने के बाद भी समता वाले राज्य और समाज की रचना अब भी दिवास्वप्न ही बनी हुई है। सबको बराबरी का हक और संपन्नता में सबकी बराबर भागीदारी की पोल तो सरकारी आंकड़ों से ही खोलते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि जहां गरीबी और असमानता व्यापक रूप से मौजूद है वहीं एक छोटा सा तबका धन-धान्य में खेल रहा है। भारत में सिर्फ दस प्रतिशत लोगों के पास देश की आधे से भी ज्यादा 57 प्रतिशत संपत्ति है जबकि देश की आधी आबादी सिर्फ 13 प्रतिशत संपत्ति पर गुजारा करने को मजबूर है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राजनैतिक दलों की प्राथमिकता केवल सत्ता पाना रह गया है। सदियों से चले आ रहे सामंती व्यवहार वाले समाज को बदल कर उसे लोकतान्त्रिक मूल्यों से पोषित करने का काम राजनेताओं और राजनीति ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। दुनिया में पहली बार राजनीति को पवित्र बनाने का प्रयत्न करने वाले महात्मा गांधी ने इसीलिए यह तजवीज दी थी कि कांग्रेस को अपने को बदल कर जमीनी स्तर पर समाज को बदलने के काम करने में लग जाना चाहिए। वे जानते थे कि एक बराबरी वाला समाज बनाने के लिए समाज सेवा करने वालों को धरती पर जड़ों में काम करके लोगों के दिलों को बदलना होगा। बदलना भी जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्रेम से। लेकिन ब्रितानवी शासन की रुखसत के बाद जब गणतंत्रिक भारत बना तब संविधान की किताब तो हम भारत के लोगों के हाथ में आ गई मगर आगे की राह दिखाने के लिए गांधी न रहे और राजनीति भटकती ही चली गई। यह विडंबना ही है कि संवैधानिक की बेहतरीन व्यवस्थाओं के बावजूद सामाजिक और आर्थिक असमानता वाला समाज देश के अमृतकाल के बाद भी नहीं बन सका है। अवसरों तथा आर्थिक असमानता तो सर्वत्र नजर आती है। राजनीति से सेवा का भाव तिरोहित हो गया है। आज राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं का जैसा स्वरूप बन गया है वह राजनीतिक अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया का ही परिणाम है। जब यह कहा जाता है कि देश में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है तब उसका आशय संविधान प्रदत्त लोकतान्त्रिक संस्थाओं के क्षरण से होता है। जिनमें संसद तथा विधानसभाएं भी शामिल हैं। लोकसभा तथा राज्यस्थान विधान सभा का पिछला पूरा कार्यकाल सदन के उपाध्यक्ष का चुनाव किये बिना बीत गया, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने को तो लोकतंत्र संविधान की किताब से चलता है मगर असल में वह उसके नियंत्रणों की नीयत से चलता है। लोकतंत्र को तानाशाही हथकंडों से नहीं चलाया जा सकता। वह अत्यंत मुलायम सहमति से चलता है। लोकतंत्र से हमने सत्तावादी राजतंत्र जैसी पुरानी सामंती व्यवस्थाओं से आजादी पाने का हक पाया है। संविधान ने अपने अनुच्छेद 15 के जरिए भारत के लोगों को बुनियादी अधिकार दिए हैं जिसमें सब नागरिकों के बीच समानता की उद्घोषणा है। लेकिन समस्या आती है प्रतिस्पर्धी राजनीति में वर्ग, जाति और सामाजिक-धार्मिक समुदायों से जो राजनीति में चुन की तरह लग गए हैं। इन सारे वर्गों में उनके आंतरिक स्वरूप में भी भेदभाव वाले कड़े पदानुक्रम मौजूद हैं। न केवल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों के बीच, बल्कि कमजोर समुदाय के भीतर भी पदानुक्रम असमानता है जो संवैधानिक प्रावधानों से नहीं सामाजिक अभियानों से ही हटाई जा सकती है। मगर राजनेताओं ने अपने हित साधने के लिए चुनावों में इस सामाजिक भेद का उपयोग करते हुए उसे अनौपचारिक रूप से संस्थागत बना रखा है। समतावादी समाज की रचना में राजनेताओं की कोई रुचि नहीं नहीं नजर आती। इससे समस्त वैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद अंत्योदय की बात कितानों में पढ़ने तक सीमित रह जाती है और व्यवहार में नहीं आती।

संविधान राज्य से अपेक्षा करता है कि वह सबके साथ समता से व्यवहार करेगा। किन्तु विडंबना यह है कि राज्य ने खुद वर्गों के पैमाने बना दिए हैं। जैसे वह एक वर्ग सरकारी कर्मियों के जीवन यापन के लिए अलग पैमाना तथा दूसरे वर्गों के लिए अलग पैमाना रखता है। देश की 70 प्रतिशत जनता गरीब है, यह प्रथममंत्री भी मानते हैं। कोई पूछे कि ऐसे में सरकारी कर्मचारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तथा कॉर्पोरेट जगत के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय गरीबों की प्रतिव्यक्ति आय से कितनी गुना अधिक है और क्यों है? मानव विकास के संकेतक लगातार इस आर्थिक असमानता की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं लेकिन दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने तथा उच्च आर्थिक विकास दर के बावजूद असमानता की यह खाई बनी हुई है। नई बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में देश के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूह अपने-अपने लिए कुछ लाभ प्राप्त करने और उन्हें सुरक्षित रखने के प्रयत्न में ही लगे नजर आते हैं। यह भी सामने दिखता है कि राजनीतिक लाभबंदी के माध्यम से राजनेता अपने-अपने समुदायों के नाम पर खुद अपने अपने परिवारों के हितों की रक्षा करने की जुगत में लगे रह कर गैरसमतावादी समाज को पुष्ट करने में लगे रहे हैं। जातियों के समूहों को भी इसी में अपना हित लगने लगता है, भले ही मलाई उन जातियों के नेता ले उड़ें। नागरिक समाज के संगठन भी इसी बहती गंगा में डूबकी लगा रहे हैं। इस खेल का सैद्धांतिक ढांचा ऐसा है कि जिनके पास अधिक शक्ति है वे लाभ का अनुपातहीन हिस्सा हासिल कर लेते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि आज भी भारतीय समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं बनी हुई हैं। जिनके पास सत्ता और धन की ताकत है सत्ता की संरचनाएं उनके अनुकूल होती चली जाती हैं। इसीलिए सभी लोग सत्ता के गतिचरों में अपनी जगह बनाने की जुगत में लगे रहते हैं। स्पष्ट रूप से, वर्तमान संस्थानों की कार्यप्रणाली आर्थिक शक्ति के असमान वितरण और राजनीतिक शक्ति तक आम जन की असमान पहुंच से संबंधित होती है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक हैसियत में भी असमानता अपनी जड़ें जमा लेती है। इसने एक दुष्चक्र पैदा कर दिया है। असमान शक्ति संरचना संस्थानों की प्रकृति और कार्यप्रणाली और उनकी नीतियों को प्रभावित करती है। यह स्थितियां देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में गरीबों की लोकतान्त्रिक भागीदारी को बाधित करती हैं।

लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, जिसमें कोई भी बालिग नागरिक निर्वाचन में खड़ा हो सकता है या खड़े हुए व्यक्तियों में से किसी एक को अपनी स्वेच्छा से मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। इसे लोकतंत्र में नागरिक की शक्ति का प्रयोग कहते हैं। नागरिक जब मतदान करता है तो वह अपना शासक नहीं चुन रहा होता है, अपना प्रतिनिधि चुन रहा होता है जिससे वह अपेक्षा होती है कि वह संसद या विधान सभाओं में जाकर नागरिक जो चाहते हैं वह बात करे। आजादी के बाद गणतंत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं हो पाया है। निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचित होकर शासक बन बैठता है और अपेक्षा करता है कि नागरिक उसके हिस्सा से व्यवहार करे। यह लोकतंत्र के शीर्षासन की स्थिति है। इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता कि उसका निर्वाचित प्रतिनिधि सदनों की कार्यवाही बाधित करे, वहां शोर मचाए या धरना दे। देश का नागरिक चाहता है कि उसका प्रतिनिधि विधि निर्माता के रूप में प्रत्येक बहस में गंभीर भागीदारी करे और सदनों में नागरिकों के जीवन से जुड़े मुद्दों के हल के लिए हां पक्ष और ना पक्ष के बीच मोटी सहमति हो, न कि झगड़ा हो। कोई उलझा हुआ मुद्दा हो तो निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों के पास आये और जानें कि आम आवाज क्या चाहता है। मगर यहाँ सवाल स्वाभाविक ही उठ खड़ा होता है कि निर्वाचन की संविधान समत व्यवस्था के बाहर प्रबुद्ध नागरिक समाज के केंद्र कहाँ है? भारतीय समाज धर्मों, जातियों और पंथों में बिखरा हुआ है। निर्वाचन प्रणाली में इस बिखराव का चतुर राजनेता लाभ उठाते हैं और एक सुंदर लोकतंत्र सपना ही बना रह जाता है। इस बिखराव से निर्वाचित राजनेताओं पर नागरिकों का अंकुश नहीं रह पाता। चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनने में भी नागरिकों की कोई भूमिका नहीं होती। जनतान्त्रिक समाज की आदर्श व्यवस्था तो यह होती है कि नागरिक ही अपने प्रत्याशी चुनें और फिर बहुमत से उनमें से किसी एक को सदनों में भेजे। मगर प्रत्याशियों के चयन का काम राजनैतिक दल करते हैं और नागरिकों को उन्हीं के चयन पर मतदान करना होता है। जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रांति की ललकार के बाद सभ्य समाजों ने ऐसे थोड़े बहुत प्रयास जरूर किये कि नागरिक अपने प्रत्याशी खुद चुनें। मगर दलबिहीन राजनीति का यह प्रयोग सम्पूर्ण क्रांति की भांति असफल रहा। इसके लिए जिस प्रकार की जमीन तैयार करने की जरूरत होती है वैसा करने वाला कोई सशक्त संगठन नहीं बन पाया। जेपी आंदोलन से निकल कर राजनीति में गये युवाओं में से भी अनेक बाद में जाकर बुरे राजनेता समित हुए। पिछले दो दशकों में ऐसे आंदोलन की उभरे जिनसे लोगों को लगा कि नई सुबह आने ही वाली है, मगर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लोकतंत्र की सफलता के लिए आम आवाज का भी संजीदा और समझदार होना अपेक्षित होता है। हमारे देश में आवाज की वैसी शिक्षा कभी हो नहीं पाई। जनता को लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए जागरूक करने में राजनीतिक दलों व उनके कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका होती है। ऐसा नेतृत्व का उभरना तभी संभव है जब आमजन लोकतंत्र और राजनीति के प्रति उदासीनता त्याग कर आभासी सोशल मीडिया पर आलोचनाओं और बहसों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर काम करे और राज्य के संचालकों से दृढ़ता से सवाल करे और जवाब मांगे।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

विश्वविद्यालय वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का निर्माण करें : राज्यपाल

कोटा, (निसं)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि विश्वविद्यालय वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का निर्माण करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों को कौशल विकास से संबंधित शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 'विकसित भारत 2047' की संकल्पना को साकार करने का आह्वान किया। राज्यपाल मंगलवार को कोटा विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति अर्थव्यवस्था को गोल्ड मेडल एवं उपाधियां प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में कन्या छात्रावास, धनवन्तरी भवन एवं बॉस्केबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट का लोकार्पण भी किया। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि नव-जीवन का प्रारंभ होता है। यह वह अवसर है जब विद्यार्थी प्राप्त शिक्षा का राष्ट्र और समाज के उत्थान में उपयोग करने के लिए तैयार होता है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने साक्षी जैन को कुलाधिपति पदक, पूजा साहू को कुलपति पदक जबकि 60 छात्र-छात्राओं स्वर्ण पदक एवं 49 विद्यावाचस्पति उपाधियां प्रदान की। कोटा विश्वविद्यालय की ओर से कुल 88 हजार 692 उपाधियां प्रदान की गईं हैं। इनमें 43 हजार 677 छात्र (49 प्रतिशत) एवं 45 हजार 15 छात्राएं (51 प्रतिशत) शामिल हैं। राज्यपाल ने



राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोटा विश्वविद्यालय में 60 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं 49 विद्यावाचस्पति उपाधियां प्रदान कीं।

51 फीसदी छात्राओं के उपाधि हासिल करने एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने पर खुशी जताते हुए कहा कि बेटियों को अवसर प्रदान किए जाएं तो वे किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। छात्राएं अपनी प्रतिभा का समुचित सदुपयोग कर निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने आह्वान किया कि छात्र-छात्राएं सामूहिक सहयोग से विकसित भारत का संकल्प पूरा करें। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा देश अपने अत्यंत काल में है।

जो-20 की अध्यक्षता भारत को मिली है और इस कार्यक्रम ने भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभारा है। भारत इस समय विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत के भविष्य को गढ़ने के सबसे प्रयास एक नए भारत की नींव का निर्माण करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में समुचित विश्व का नेतृत्व करेगा। राज्यपाल ने कहा कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास आधारित शिक्षा पर केन्द्रित है। यह रोजगारोन्मुखी

होने के साथ चरित्र-निर्माण, ज्ञान-विज्ञान व आध्यात्मिक विकास के साथ देश और समाज की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ी है। कोटा विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्रेडिट आधारित सेमेस्टर प्रणाली लागू करने तथा इस प्रेडिग प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साथ-साथ नैतिक मूल्य आधारित कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की उन्होंने

कोटा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित

साराहना की। उन्होंने कहा कि कोटा विश्वविद्यालय ने स्वयंपाटी विद्यार्थियों के लिए सतत मूल्यांकन को जोड़कर प्रदेश में एक अनूठी पहल की है। समारोह की शुरुआत में राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिकाएं एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया। दीक्षांत भाषण में वनस्थली विद्यापीठ की कुलपति प्रो. ईना आदित्य शास्त्री ने कहा कि शिक्षा का ध्येय मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य का चरित्रिक निर्माण तथा ज्ञान के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का विकास है। विश्वविद्यालय की कुलपति, प्रो. नीलिमा सिंह ने विश्वविद्यालय प्रति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में कुलपति प्रो. नीलिमा सिंह ने राज्यपाल का स्वागत किया। अंत में कुलसचिव प्रो. रीना दाधिच ने धन्यवाद ज्ञापित किया। दीक्षांत समारोह में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रो. एस्के सिंह, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अणु कुमार व्यास सहित कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, विधि संकाय व जीव विज्ञान के अधिष्ठाता उपस्थित थे।

ग्वार की अवैध खेती से वन्यजीवों के संरक्षण में आई बाधा

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर जिले में वन विभाग की जमीन पर अतीकर्मियों द्वारा ग्वार की खेती कर के अर्बों रूपसे कमाने के दौरान वन्यजीवों के जीवन पर भारी संकट आया उस दौरान ग्वार के बावजूद 6 गुना बढ़ कर 3 सौ सप्प प्रति किलोग्राम हो जाने से स्वार्थी लोगों ने वन विभाग के कर्मचारियों से मिल कर वन्यजीवों की जमीन को भी नहीं बक्सा सरकारी जमीन पर वन्यजीवों के शत्रु बन कर कानून को अपने हाथ में लेकर गोडावण व अन्य जमीनों के संरक्षण को धता बताते हुए कृत्य करने वालों को कोई आंच नहीं आई।

हालांकि वन्य एरिया में लगी हाइड्रेशन लाइन भी गोडावण की मौत के लिए जिम्मेदार है। जिसे लेकर वन्यजीव प्रेमियों द्वारा कई बार विरोध भी जताया जा चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन हाइड्रेशन लाइनों को अंडरटाउंड करने को लेकर कई बार

पारबंदी की है। लेकिन इसके बावजूद अब तक हाइड्रेशन लाइनों को अंडरटाउंड नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गोडावण व अन्य जमीनों के संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करके जैसलमेर भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति का गठन कर उन्हें वन्यजीवों के संरक्षण के उपायों के साथ ही ओवरहेड व अंडरटाउंड केबल व दायरे का निर्धारण करने का काम सौंपा। 30 जून को समिति के प्राथमिकी जैसलमेर पहुंचे। उन्होंने सोमवार को फील्ड विजिट कर अपनी रिपोर्ट तैयार की।

गौरतलब है कि अब तक हाइड्रेशन लाइन से टकराने पर करीब 9 गोडावणों की मौत हो चुकी है। 2021 में पर्यावरणविद और वन्यजीव विशेषज्ञ एमके रंजित ने एक रिट याचिका पेश कर समिति के गठन की बात की थी। उन्होंने ऊर्जा संयंत्रों के पास हाइड्रेशन वाले तारों से टकराने

पर वन्यजीवों व गोडावण की मौत पर प्रकाश डाला था। जिस पर मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में सात सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। जैसलमेर के डीएनपी एरिया के आस पास सोलर प्लांट आ गए हैं। जिससे नए जीएसएस का निर्माण किया जा रहा है। इन्हीं जीएसएस तक बिजली आपूर्ति करने के लिए हाइड्रेशन लाइनें बिछाई गई हैं। डीएनपी क्षेत्र में कुछ जगह अंडरटाउंड केबल करना असंभव है।

छबड़ा से कडैयानोहर को जोड़ने वाली संपर्क सड़क का हाल बेहाल, आवागमन बाधित

छबड़ा (निसं)। आज भी ग्रामीण अंचलों में सड़क की समस्या महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। छबड़ा से कडैयानोहर को जोड़ने वाली संपर्क सड़क का हाल खस्ता होने के कारण लोग जोखिम में डालकर वाहन चलाने को मजबूर हैं। छबड़ा से कडैयानोहर को जोड़ने वाली संपर्क सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण खांकरा, कडैयानोहर, कुण्डी, पटना, लोधपुरिया, अमीनपुरा, खेरखेडाभाथूराम, युसुफपुरा आदि गांव के ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है और यह समस्या वर्षों के दिनों और अधिक बढ़ जाती है। इस क्षतिग्रस्त सड़क पर से वाहन लेकर चलना तो दूर की बात है पैदल चलना भी मुसीबत से कम

नहीं है। कहीं-कहीं तो इस सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे खुले हैं। राहगीर इस रास्ते से जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़क का खस्ताहाल रोजाना हादसों को न्यौता दे रहे हैं। सड़क जर्जर होने के कारण शिक्षक, ग्रामीण कमर दर्द से पीड़ित होने लगे हैं।

स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को परेशानी:- ग्रामीणों के अनुसार बारिश के सीजन में स्कूल आते-जाते समय इस क्षतिग्रस्त सड़क से गुजरने वाले विद्यार्थी कीचड़ में फिसल कर अनेकों बार गिर चुके हैं। उनकी न्यूनीफार्म तक खराब हो जाती है। मार्ग में पानी जमा होने व दलदल की वजह से विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी

संख्या घटती है। स्कूलों के आसपास भी पानी जमा होने से बच्चों की सुरक्षा में बाधा पड़ती है।

मरीज-चिकित्सालय तक नहीं पहुंच पाते:- ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो गांव तक एम्बुलेंस नहीं आ पाती। मुख्यालय तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात में जहरीले जीव जंतुओं का डर हमेशा बना रहता है। इसके अलावा आसपास के गांवों की आबादी भी इस खराब सड़क की वजह से परेशानी झेल रही है। यह सड़क गांव के लोगों के लिए मुख्य सड़क है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण जरा सी बरसात में यह मार्ग न केवल कीचड़ में तब्दील हो जाता, बल्कि सामान्य मौसम में भी ऊबड़ खाबड़ के हालात बन रहे हैं। बारिश की वजह से कई स्थानों पर जलभराव जैसी नौबत बन जाती है।

पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षा का मौसम उनके लिए वनवास जैसा है। ना साइकिल चल पाती है ना दोपहिया वाहन।

	मेघ व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक कार्यों से अटक हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।		सिंह व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।		धनु स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिवसों में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है।
	वृष मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।		कन्या नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।		मकर व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होगा। नैकरोंपणा व्यक्तियों को भागदंड से राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
	मिथुन आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। नैकरोंपणा व्यक्तियों को भागदंड रहेगी। स्वास्थ्य के संबंध में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।		तुला व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनीं रहेंगी। व्यावसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बने कार्य बिगड़ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी हो सकती है।		कुंभ घर-परिवार में शुभ-मौलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।
	कर्क आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बने लगे।		वृश्चिक परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।		मीन परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

राशिफल बुधवार 3 जुलाई, 2024

आषाढ मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2081, रोहिणी नक्षत्र रात्रि 4:07 तक, शूल योग प्रातः 9:01 तक, तैतिल करण प्रातः 7:11 तक, चन्द्रमा वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मेघ, बुध-कर्क, गुरु-वृष, शुक्र-मिथुन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से सम्पूर्ण दिन-रात है। आज प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत (जैन) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:06 तक, शुभ 10:48 से 12:30 तक, चर 3:56 से 5:18 तक, लाभ 5:18 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:41, सूर्यास्त 7:20



पंडित अनिल शर्मा